संख्या-03/2021/888/कनिप्र/26-3-2020-4(20)/2004

प्रेषक,

राज रतन,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा मे,

निदेशक,
समाज कल्याण,
उत्तर प्रदेश लखनऊ।

कल्याण नियोजन प्रकोष्ठ — लखनऊ: दिनांक : 19 जनवरी,2021
समाज कल्याण विभाग

विषय: लाण्ड्री एवं ड्राईक्लीनिंग योजनान्तर्गत चालू वित्तीय वर्ष 2020-21 हेतु ब्याजमुक्त ऋण की मद में धनराशि की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम के पत्रांक-1425/लेखा अनुभाग/2020-21 दिनांक 23 नवम्बर,2020 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश् हुआ है कि लाण्ड्री एवं ड्राईक्लीनिंग योजनान्तर्गत चालू वित्तीय वर्ष 2020-21 में निर्धारित लक्ष्यों की पूर्ति हेतु ब्याजमुक्त ऋण मद में व्यवस्थित रू0 400.40 लाख (रूपये चार करोड़ चालीस हजार मात्र) की धनराशि निम्नलिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन अवमुक्त किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है:-

1- उपर्युक्त धनराशि आप द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित बीजक के माध्यम से प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम द्वारा आहरित कर निर्धारित लक्ष्यानुसार जनपदों को आवंटित की जायेगी।
2- प्रश्नगत धनराशि का व्यय भारत सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा योजना के संबंध में निर्गत दिशा-निर्देशों/व्यवस्थाओं के अधीन ही आहरित/व्यय की जायेगी।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

3- यह भी सुनिश्चित किया जाय कि प्रश्नगत कार्य किसी अन्य कार्य योजना में सम्मिलित नहीं है तथा इस हेतु पूर्व में किसी अन्य योजना/स्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं की गयी है।

4- प्रश्नगत वित्तीय स्वीकृति जिस कार्य/मद हेतु की जा रही है उसका उपयोग नियमानुसार उसी कार्य/मद हेतु किया जायेगा तथा यह भी सुनिश्चित किया जायेगा कि प्रस्तावित कार्यो की द्विरावृत्ति नहीं हो रही है, साथ ही वित्त बजट अनुभाग-2 के शासनादेश संख्या-बी-2-2528/दस-2014-10/77 दिनांक 26-08-2014 में विहित व्यवस्थाओं का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

5- उक्त स्वीकृत धनराशि को व्यय/उपभोग किये जाने से पूर्व यह सुनिश्चित किया जायेगा कि योजनान्तर्गत पूर्व में अवमुक्त धनराशि पी.एल.ए./ डिपाजिट खातों आदि में अप्रयुक्त उपलब्ध न हो। स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय/उपयोग योजना हेतु निर्गत नियमावली/स्थाई आदेशों में दी गयी व्यवस्था के अनुसार किया जायेगा तथा एस.सी.एस.पी./टी.एस.पी. के दिशा निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

6- प्रश्नगत धनराशि किसी भी दशा में सावधि जमा के रूप में नहीं रखी जायेगी। प्रबन्ध निदेशक उ0प्र0अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम जनपदों को आवंटित समस्त धनराशि की सूचना शासन को शीघ्र उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेगें। इन आदेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

7- उपर्युक्त धनराशि शासन द्वारा इस संबंध में समय-समय पर निर्गत शासनादेशों में निर्धारित नियमों के अनुसार व्यय की जायेगी और व्यय की गयी धनराशि तथा लाभार्थियों की सूची एवं अन्य विवरण निर्धारित रूप पत्रों पर जिला समाज कल्याण अधिकारी (विकास)/ पदेन जिला प्रबन्धक, उ0प्र0अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम द्वारा प्रबन्ध निदेशक, उ.प्र.अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम तथा शासन को भी उपलब्ध कराये जायेगें। स्वीकृत धनराशि से अधिक व्यय किसी भी

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

दशा में नहीं किया जायेगा और न ही किसी अन्य मद में धनराशि का उपभोग शासन की अनुमति के बिना किया जायेगा। इसके लिए संबंधित जनपदों के जिला प्रबन्धक/सहायक प्रबन्धक व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होगें।

8- उपरोक्त धनराशि के उपभोग प्रमाण-पत्र नियमानुसार शासन तथा महालेखाकार उ0प्र0 प्रयागराज को यथा समय उपलब्ध कराये जायेगें। इस अनुदान के उपभोग पर वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड-5 भाग-1 के अध्याय-16-ए के नियम लागू होगें।

2- उपर्युक्त पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2020-21 के आय-व्ययक की अनुदान संख्या-083 समाज कल्याण विभाग (अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना) के लेखाशीर्षक-"6225-अनुसूचित जातियों,अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गो के कल्याण के लिए कर्ज-01-अनुसूचित जातियों का कल्याण-789-अनुसूचित जातियों के लिये विशेष घटक योजना-03-धोबी समाज के व्यक्तियों को ब्याज रहित ऋण-30-निवेश/ऋण" के नामें डाला जायेगा।

3. प्रश्नगत धनराशि के निर्गत किये जाने के संदर्भ में वित्त विभाग के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-1/2020-बी-1-149-दस/2020-231/2020 दिनांक 24 मार्च,2020, शासनादेश संख्या-5/2020/बी-1-196/दस-2020-231/2020 दिनांक 11-04-2020, एवं शासनादेश संख्या-10/2020/बी-1-564/दस-2020-231/2020 दिनांक 29-09-2020 में निर्धारित दिशा निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

4. यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-ई-4-50ए/दस/2021 दिनांक 15 जनवरी,2021 में प्राप्त सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

राज रतन
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

पृ0 संख्या-03/2021/ 888 (1)/क.नि.प्र./26-3-2020 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- महालेखाकार,उ0प्र0 प्रयागराज।

2- संयुक्त सचिव, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार, शास्त्री भवन, नई दिल्ली।

3- निदेशक, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार, शास्त्री भवन, नई दिल्ली।

4- प्रबन्ध निदेशक, उ.प्र. अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम, महानगर, लखनऊ।

5- मुख्य कोषाधिकारी कैसरबाग,लखनऊ

6- वित्त(व्यय-नियन्त्रण) अनुभाग-4/वित्त संसाधन(केन्द्रीय सहायता) अनुभाग,उ.प्र. शासन।

7- बजट प्रकोष्ठ, समाज कल्याण विभाग।

8- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

अनिल कुमार सिंह
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।